नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन : योगी

6 कलेक्टर साहब, थाने में नहीं होती सुनवाई

7 वैश्विक व्यापार में संतुलन की दरकार

8 मियामी ओपन के फाइनल में सबालेंका और गॉफ

एक नजर में

जम्मू-कश्मीर विस में हाथापाई

जम्मू कश्मीर . जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भारी हंगामा हुआ, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया. वे खामेनेई की तस्वीरें लेकर सदन में पहुंचे और ईरान के समर्थन में नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे. जवाब में भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने राहुल गांधी को 'पप्पू' कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की और हाथापाई हो गई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान मुद्दे पर कहा कि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया है और इसे मानवता के खिलाफ बताया. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी ईरान के साथ खड़ी है और खामेनेई की हत्या की निंदा करती है.

टीम इंडिया की तरह मिलकर करें काम

पश्चिम एशिया संकट पर मोदी ने की राज्यों के सभी सीएम से बात

नई दिल्ली, 27 मार्च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ पश्चिम एशिया में हालात और भारत पर उनके संभावित असर को लेकर तैयारियों की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि 'टीम इंडिया' के तौर पर मिलकर काम करते हुए देश इस चुनौती का सामना सफलता से करेगा.

प्रधानमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं में आर्थिक और व्यापार में स्थिरता बनाए रखना, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और इंडस्ट्री व सप्लाई चेन को मज़बूत करना शामिल बताया. उन्होंने राज्यों से सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने और जमाखोरी व मुनाफ़ाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की.

प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर, विशेषकर फर्टिलाइज़र के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि किसानों को

आने वाले खरीफ सीजन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. उन्होंने राज्यों को कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने, एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्टनेस बनाए रखने और बदलते हालात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूत कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा. शिपिंग, ज़रूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बॉर्डर और तटीय राज्यों पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई.

प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी और अफवाहों के खिलाफ आगाह करते हुए सही और भरोसेमंद जानकारी फैलाने पर जोर दिया.

मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार की तैयारियों और फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसलों की सराहना की. उन्होंने भरोसा जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हालात स्थिर हैं. सभी सीएम ने केंद्र के साथ मिलकर हालात को प्रभावी ढंग से मैनेज करने का वादा दोहराया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा अपनाए गए सहयोगी कदमों का अनुभव मौजूदा संकट से निपटने में मददगार साबित होगा.

मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे जेवर में नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम में गौतमबुद्धनगर समेत सात जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे. लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहेंगे. सुरक्षा और कार्यक्रम संचालन के लिए पांच हेलीपैड बनाए गए हैं.

एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटने से राहत

नई दिल्ली, 27 मार्च. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गई है. इसका उद्देश्य

कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल को सीमित करना उद्देश्य

अमेरिका, इजरायल-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है.

सरकार डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है. इसके अलावा, केंद्र ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की है. सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी करने पर सभी मात्रियों के आभार जाताया है. उम्मीद की जा रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) बढ़ते नुकसान की भरपाई के लिए इस कटौती को स्वयं समायोजित करेंगी.

अनुमान है कि ओएमसी को वर्तमान में ईंधन की बिक्री पर लगभग 48.8 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है. मध्य्‌ पूर्व में तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है.

बीते एक महीने में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम करीब 40 प्रतिशत बढ़ चुका है. फिलहाल यह 101 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है.

> सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है. सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे 'जानबूझकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान' से गुमराह न हों, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है.

सीएम ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कटौती का किया स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम एशिया में इन दिनों हो रही भारी उथल-पुथल के बीच भारत सरकार द्वारा घरेलू खपत के लिए डीजल-पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती और डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर एवं हवाई ईंधन (एटीएफ) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाये जाने का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में बेहद महत्वपूर्ण है. इससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा और घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ें, लॉकडाउन नहीं लगेगा : निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते थे कि (पेट्रोलियम) के खुदरा मूल्य बढ़ें. वित्त मंत्री ने ईंधन की कमी को लेकर देश में कोविड महामारी के दौर जैसा लॉकडाउन लगाने की चर्चाओं को भी खारिज किया और कहा कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होगा. सीतारमण ने डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में दस-दस रुपये की कटौती के ताजा निर्णय के बारे में कहा, 'प्रधानमंत्री चाहते थे कि उपभोक्ता कीमतें न बढ़ें.' वित्त मंत्री ने ईंधन पर शुल्क में कमी की सराहना की. उन्होंने लॉकडाउन की चर्चा पर कहा, 'मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा...' 'मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे

हैं कि लॉकडाउन होगा और ईंधन की कमी हो जाएगी. ये बातें बेबुनियाद हैं.' श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की लॉकडाउन जैसी टिप्पणियाँ चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा, 'वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था. मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने कोविड में देखा था.' पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती पर उन्होंने कहा, 'पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि पेट्रोल, डीज़ल और एटीएफ (विमान ईंधन) की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वैश्विक स्थिति के कारण इनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए.

ट्रम्प ने हमले को 10 दिन किया स्थगित

वाशिंगटन, 27 मार्च. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए रोक दिया है.

ट्रम्प ने कहा कि वे इस प्रक्रिया को छह अप्रैल को पूर्वी समयानुसार रात आठ बजे तक के लिए स्थगित कर रहे हैं.

> ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, 'ईरानी सरकार के अनुरोध पर, मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि को 10 दिनों के लिए सोमवार, छह अप्रैल को रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक रोक रहा हूं.' उन्होंने दोहराया कि बातचीत जारी है और फर्जी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.

दायरा बढ़ाया

वॉशिंगटन/तेलअवीव/तेहरान. पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर ग्रिड और ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की अपनी अंतिम सीमा को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने 6 अप्रैल 2026 तक ईरान पर किसी भी बड़े हमले को टालने की घोषणा की.

एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा पश्चिम एशिया से करेंगी उड़ानों का परिचालन

नयी दिल्ली, 26 मार्च. भारतीय विमान सेवा कंपनियों एयर इंडिया, इंडिगो अकासा एयर ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया और भारत के बीच उड़ानों के परिचालन की जानकारी दी है. एयर इंडिया अपनी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ शुक्रवार को भारत और पश्चिम एशिया के बीच कुल 22 उड़ानों का परिचालन करेगी. इसमें 14 नियमित और आठ विशेष उड़ानें शामिल हैं.

तुंगुस्का मिसाइल और पी8आई विमान 858 करोड़ का अनुबंध

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए विमान रोधी तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद और लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8आई के निरीक्षण (डिपो स्तर) के लिए कुल 858 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर यहां रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किये गये. यह समझौता भारत-रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा.

बालेंद्र शाह बने नेपाल के प्रधानमंत्री

नेपाल के सबसे युवा पीएम
47वें पीएम पद की शपथ ली

काठमांडू, 27 मार्च. बालेन्द्र शाह ने शुक्रवार को काठमांडू स्थित शीतल निवास में नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. 35 वर्षीय शाह देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिससे नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है.

शपथ ग्रहण समारोह पारंपरिक और विशेष रहा, जिसमें शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार और बौद्ध अनुष्ठान शामिल हुए.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने शाह को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को शपथ लेने पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि शाह का चयन नेपाल की जनता के उनके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाता है. मोदी ने अपने संदेश में भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने की बात कही और दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश सहयोग और मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

सेना का आधुनिकीकरण ▶ राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2.38 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी

भारत की सैन्य ताकत होगी मजबूत

नयी दिल्ली 27 मार्च . सरकार ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढाने तथा उनके आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को जरूरत के आधार पर खरीद की मंजूरी दी है जिनमें वायु सेना के लिए मध्यम परिवहन विमान, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 मिसाइल प्रणाली, मानव रहित मारक विमान तथा सुखोई- 30 लड़ाकू विमानों के एयरो इंजन एग्रीगेटर के रखखाव

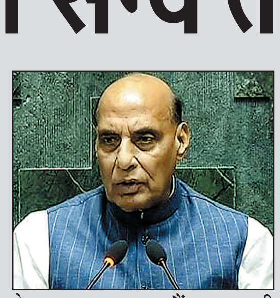

के प्रस्ताव प्रमुख हैं। साथ ही इनमें सेना के लिए वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली, कवच भेदी टैंक गोला-बारूद, उच्च क्षमता रेडियो रिले, धनुष तोप प्रणाली तथा रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन सौदों को जरूरत के आधार पर खरीद की मंजूरी दी गयी। वायु सेना के पुराने हो चुके मालवाहक विमानों एएन-32 और आईएल-76 परिवहन बेड़े के स्थान पर मध्यम परिवहन विमान को बेड़े में शामिल करने से वायु सेना की रणनीतिक, सामरिक और परिचालन वायु परिवहन आवश्यकता कई गुना बढ जायेगी।

6.73 लाख करोड़ के 55 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6.73 लाख करोड़ रुपये की राशि के 55 प्रस्तावों को आवश्यकता के आधार पर खरीद की मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2.28 लाख करोड़ रुपये की राशि के प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।